आज बुधवार १५ नवम्बर, २०१७ सौर २९ कार्तिक सं. २०७४ वि.

सुभाषित *आपत्तियोंकी कोई मर्यादा नहीं होती, उनका न कोई निमित्त होता है और न ही कोई कारण परन्तु प्रारब्धके चलते धर्म ही पाप और पुण्यके फलस्वरूप सुख और दुखोंमें बंट जाता है।* ❐ *विदुर नीति*

प्रदूषण पर न्यायालय सख्त

उत्तर भारतमें प्रदूषणकी गम्भीर स्थितिको देखते हुए सर्वोच्च न्यायालयने सोमवारको केन्द्र सरकारके अतिरिक्त दिल्ली, पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेशकी सरकारोंको नोटिस जारी करते हुए प्रदूषणको नियन्त्रित करनेके लिए प्रभावी कदम उठानेका सख्त निर्देश दिया है। मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति दीपक मिश्रकी अध्यक्षता वाली तीन सदस्यीय पीठने अधिवक्ता आर.के. कपूरकी याचिकापर नोटिस जारी करनेके साथ ही स्पष्ट किया है कि शीर्ष न्यायालय प्रदूषणके मामलेको नजरअन्दाज नहीं कर सकता है। इसके अतिरिक्त न्यायालयने यह भी कहा है कि वह प्रदूषणके मामलेमें अन्य अदालतमें लम्बित किसी मुकदमोंकी सुनवाईपर भी रोक नहीं लगाने जा रहा है। निश्चित रूपसे सम्पूर्ण उत्तर भारतके सभी राज्योंमें प्रदूषण भयावह और प्राणघातक स्थितिमें है। लेकिन दुर्भाग्यकी बात है कि इसे नियन्त्रित करनेमें केन्द्र और राज्य सरकारें पूरी तरहसे विफल हैं। किसी भी स्तरपर यदि कोई कार्य हुआ होता तो लोग न्यायालयकी शरणमें क्यों जाते। इस मामलेमें गम्भीर लापरवाही अतीतमें भी बरती गयी हैं और उसकी बराबर उपेक्षा की जा रही है। प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड नाम मात्रका है। उसकी कार्य पद्धतिकी विश्वसनीयता ही समाप्त हो गयी है। प्रदूषणको बढ़ानेमें धूलका काफी योगदान होता है लेकिन न तो पानीका छिड़काव होता है और न ही उसकी सफाई। शीर्ष न्यायालयने स्पष्ट टिप्पणी की है कि प्रदूषणसे सम्बन्धित मामलोंको नजरअन्दाज नहीं किया जा सकता लेकिन जिनपर प्रदूषण नियन्त्रणकी जिम्मेदारी है वे पूरी तरह निष्क्रिय हैं। प्रदूषण नियन्त्रणके लिए आवण्टित धनराशि कहां चली जाती है, यह जांचका विषय है। सभी राज्य सरकारों और केन्द्र सरकारकी जिम्मेदारी है कि प्रदूषणके खिलाफ युद्ध स्तरपर कार्य करें। खेतोंमें पराली जलानेपर अंकुश लगानेके लिए दण्डात्मक कदम उठाने होंगे। साथ ही सार्वजनिक परिवहन साधनोंको बढ़ावा दिया जाय। ऐसे मोटर वाहन जो कार्बन डाई आक्साइडका अधिक उत्सर्जन करते हैं, उन्हें तत्काल सीज किया जाय। प्रदूषणके निगरानी तंत्रको भी सतत सजग दृष्टि रखनी होगी। आम जनताकी भी प्रदूषण नियन्त्रणमें बड़ी भूमिका है। इसके लिए उन्हें भी सक्रिय होना होगा।

एक और क्रान्तिकारी कदम

भारत लगातार प्रगतिकी ओर अग्रसर है। अन्तरिक्ष विज्ञान हो, दूरसंचार क्रान्ति अथवा अन्य क्षेत्र। सभी क्षेत्रोंमें विकासने गति पकड़ी है। दुनिया २०३० तक भारतको विश्वकी तीसरी ताकतके रूपमें देख रही है। दूरसंचारके क्षेत्रमें भारतने विकासके नये आयाम स्थापित किये हैं। मोबाइलसे लेकर इण्टरनेटतक आम लोगोंकी पहुंचमें है। इन सबके बाद भी लाखों गांव ब्राडबैण्डकी सुविधासे वंचित हैं। निजी कम्पनियोंकी प्रतिस्पर्धाने आम लोगोंको राहत दी है। इसी क्रममें सोमवारको दूरसंचार राज्यमंत्री मनोज सिन्हाने सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री रविशंकर प्रसाद एवं मानव संसाधन विकास मंत्री प्रकाश जावड़ेकरके साथ भारत नेट योजनाकी शुरुआत की। इसमें ३१ हजार करोड़की लागतसे मार्च २०१९ तक डेढ़ लाख गांवमें हाई स्पीड ब्राडबैण्डकी सुविधा उपलब्ध होगी। छह माहतक गांवोंमें सेवा निःशुल्क होगी। रिलायंस जियोने ३० हजार गांवमें ब्राडबैण्ड लगानेके लिए सरकारको १३ करोड़ अग्रिम भुगतान किया। कम्पनीके अनुसार ३० हजार गांवमें ब्राडबैण्डकी सुविधा देनेके बाद और गांवमें इस सेवाका विस्तार किया जायगा। इसके अतिरिक्त भारतीय एयरटेलने ३०५०० ब्राडबैण्डके लिए पांच करोड़का भुगतान किया। वोडाफोन और आइडियाने भी क्रमशः ११ और पांच लाखका भुगतान किया। दूरसंचारमंत्री मनोज सिन्हाने कहा है कि ब्राडबैंण्ड लगानेवाली कम्पनियोंको रियायती दरपर उपकरण उपलब्ध करवाये जायंगे। वर्तमानमें ४८ हजार गांवमें ब्राडबैण्ड सेवा काम कर रही है। पूरे देशमें ब्राडबैण्डकी सेवा उपलब्ध होनेके बाद निश्चित ही अध्ययन, अध्यापन सहित सभी क्षेत्रोंमें इसका लाभ मिलेगा। अबतक दूरसंचार कम्पनियों द्वारा दी जा रही सेवा ठीकसे नहीं मिल पा रही है। मोबाइलपर कालड्राप तो आम बात है। इण्टरनेटपर ४जीकी सुविधा २जीकी रफ्तार भी नहीं पकड़ती। ऐसी स्थितिमें उपभोक्ताको पैसेके साथ समय भी गंवाना पड़ता है। सरकारको पहले वर्तमान सुविधाओंकी ठीक करवानेकी कोशिश करनी चाहिए। गुणवत्तापूर्ण सुविधाके बिना दूरसंचार क्षेत्रकी क्रान्ति सफल नहीं हो सकेगी।

लोक संवाद

पाकिस्तान से दोस्ती और आतंकवाद

महोदय,- पाकिस्तान और चीनसे दोस्ती और वार्ताका क्रम अब समाप्त होना चाहिए। दोस्ती और जेहादी आतंकवाद एक साथ नहीं चल सकते। जो तोके काट बोये ताके भोके तू भला वाली कहावत जबतक पूरी तरह चरितार्थ नहीं होती। तबतक हमारी सेना पड़ोसी मुल्क चाइना और पाकिस्तानके अन्दर घुसकर उनकी नापाक कारगुजारियोंको संज्ञानमें लेकर उनकी बाह नहीं तोड़ती तबतक यह दोनों देश भारतमें घुसकर धान बोते रहेंगे। एक सर्जिकल स्ट्राइक काफी नहीं है। पाकिस्तानके लिए ऐसी हर माह एक सर्जिकल स्ट्राइक चाहिए। कश्मीरमें सुरक्षाबलोंपर आज भी पत्थरबाजी हो रही है। उनके हथियार छीने जाते हैं। उनको गाली दी जाती है। ऐसे पत्थरबाजोंको उनके घरमें घुसकर मारा जाय, उनके मनोबलको तोड़ा जाय। जो भी नागरिक प्रगतिशील राजनेता, पत्रकार, साहित्यकारके घरोंमें जाकर अलगाववादियोंके साथ हमदर्दी जताय या देशविरोधी बयान दागे सबसे पहले ऐसे दागी नेताओंको जेलमें डाला अलगाववादी संघटनोंपर जो कश्मीरकी आजादीकी मांग ऐसे संघटनोंको प्रतिबन्ध लगाकर उनके नेताओंपर देशद्रोहके मुकदमे चले। मोदी सरकार कश्मीरके लिए सराहनीय प्रयास कर रही है। पूर्व कांग्रेस सरकारसे बेहतर है। हम सब चाहते हैं घाटीसे उजड़े चार लाखसे ज्यादा हिन्दुओंको सम्मानजनक सुरक्षित वापसी हो। -आनन्द मोहन भटनागर, लखनऊ।

सर्वस्वीकार्य नहीं है हुर्रियत

कश्मीरमें केंद्र सरकारके वार्ताकार दिनेश्वर शर्मा हुर्रियत नेताओंसे भी बातचीतके पक्षधर हैं, लेकिन हुर्रियतमें मीरवाइज, उमर फारूक, सैयद अली शाह गिलानी, यासीन मलिक सरीखे बड़े नेताओंने बातचीतसे इनकार कर दिया है। उनका सवाल है कि वार्ताकारकी हैसियत क्या है कि उनसे बातचीत की जाय?

❐ राजेश माहेश्वरी

हुर्रियत अलगाववादी दोहरा रहे हैं कि उन्होंने प्रधान मंत्रीके तौरपर अटल बिहारी वाजपेयी और स्वराष्ट्रमंत्रीके तौरपर लालकृष्ण आडवाणीसे बातचीत की थी। पूर्व प्रधान मंत्री डा. मनमोहन सिंहके साथ भी तीन बार बातचीत हुई। क्या दिनेश्वर शर्मा उनसे बड़े दानिशमंद हैं, जो उनसे बातचीत की जाय? वार्ताकार कश्मीरको क्या दे सकते हैं? पहलेके वार्ताकार क्या कर पाये, यह एक इतिहास है, जिसका खुलासा देशके सामने किया जाना चाहिए। हुर्रियतसे संवादकी इच्छाने उसे नये सिरेसे प्रासंगिक बना दिया है। जबसे राष्ट्रीय जांच एजेंसीने हुर्रियत नेताओंपर छापोंकी बौछार की है और यह तथ्य भी सामने आया है कि आतंकी फंडिंगके तहत एनआईएने ३६ करोड़ रुपयेसे ज्यादाकी राशि पकड़ी है, तबसे हुर्रियत बचावकी मुद्रामें थी। उनकी छवि हवालाबाज, दलाल, चोर-उचक्कोंकी बन गयी थी। कई नेता हिरासत या जेलमें भी हैं, लेकिन दिनेश्वर शर्माने बातचीतकी इच्छा व्यक्त कर हुर्रियतको कश्मीरका चेहरा बना दिया है। खुद हुर्रियत प्रवक्ताने बयान जारी कर कहा था कि सरकारके प्रतिनिधिने शर्मासे बातचीतके लिए दबाव बनाते हुए दो बार सैयद अली शाह गिलानीसे मुलाकात भी की। याद रहे दिनेश्वर शर्माकी वार्ताकारके तौरपर नियुक्तिकी सचाई यह है कि जम्मू तथा लद्दाखकी जनता पहलेके वार्ताकारोंकी नियुक्तिका हमेशा स्वागत करती रही है लेकिन वह भी इस बार इसलिए मायूस नजर आ रहे हैं क्योंकि उनका सवाल था कि पहलेके वार्ताकारोंकी संस्तुतियोंको लागू न कर नये वार्ताकारको क्यों नियुक्त किया गया है। वह कहते थे कि वार्ताकारोंकी नियुक्ति कश्मीर मसलेको नहीं सुलझा सकती। शर्माके राज्यके दौरेसे दो दिन पहले ही सैयद अली शाह गिलानीने बातचीतसे समस्याका हल निकालनेकी बात कही थी लेकिन वह सीधे केंद्र सरकारके साथ बिना शर्त बातचीतके पक्षमें थे।

> यह हुर्रियतकी खुशफहमी है कि वही कश्मीरके असली और सच्चे प्रतिनिधि हैं, जबकि ऐसा बिलकुल भी नहीं है। कश्मीरके साथ जम्मू और लद्दाखके क्षेत्र भी जुड़े हैं। जम्मूके डोगरा, कश्मीरके ही पंडित और लद्दाखके लद्दाखी लोग हुर्रियतके साथ नहीं हैं। हुर्रियत श्रीनगरमें और आसपास सिर्फ एक ही तबकेकी बात करती रही है। हुर्रियत नेता कश्मीरपर बातचीतके पक्षधर हैं-भारत, पाकिस्तान और हुर्रियतकी व्यवस्था संयुक्त राष्ट्रसे लेकर किसी भी समझौतेमें नहीं है। हुर्रियतवाले जिस संयुक्त राष्ट्र प्रस्तावकी दुहाई देते रहे हैं, उसमें भी भारत-पाकिस्तानका ही जिक्र है। कोई तीसरा पक्ष नहीं। प्रस्तावपर कारवाईसे पहले यह प्रावधान है कि पाकिस्तान अपने कब्जेके भारतीय हिस्सेको भारतको पहले लौटायगा, उसके बाद कोई संवाद या कारवाई शुरू होगी।

इतिहासके पन्ने पलटे तो कश्मीरकी उलझी समस्या सुलझानेकी पहली कोशिश वर्ष १९९० में उस समय आरंभ हुई थी जब एक साल पहले कश्मीरमें आतंकवादने अपने पांव पसारे थे। तब कश्मीरमें शांति लानेका प्रयास मार्च १९९० में तात्कालीन प्रधान मंत्री राजीव गांधीके नेतृत्वमें कश्मीर आये एक प्रतिनिधिमंडलने किया था। उसके बाद तो ऐसे प्रयासोंका क्रम अनवरत जारी है। राजीव गांधीके दौरेके तुरंत बाद केंद्र सरकारने अलगाववादियोंको वार्ताकी मेजपर लानेके लिए दो और प्रयास किये। पहला औपचारिक प्रयास अप्रैल २००१ में पूर्व केंद्रीय मंत्री के.सी. पंतके नेतृत्वमें उस समय हुआ जब उन्हें केंद्र सरकारने पहला आधिकारिक वार्ताकार नियुक्त किया। हालांकि अलगाववादी नेताओंने के.सी. पंतसे मिलनेसे इनकार कर दिया था परन्तु अलगाववादी नेता शब्बीर अहमद शाहने जरूर उनसे कश्मीर मसलेको सुलझानेकी खातिर मुलाकात कर अपने सुझाव दिये थे। तब शब्बीर शाह हुर्रियत कांफ्रेंसमें शामिल नहीं हुए थे। इन मुलाकातों और पहले वार्ताकारके प्रयास कोई नतीजा नहीं दे पाये तो वर्ष २००२ में उन्हें बंद कर दिया गया। हालांकि जिस साल वर्ष २००२ में के.सी. पंतने वार्ताकारके रूपमें अपने प्रयास रोक दिये थे तब वरिष्ठ वकील राम जेठमलानीके नेतृत्वमें अगस्त २००२ में आठ सदस्यीय कश्मीर कमेटीने जन्म लिया जिनका मकसद भी अलगाववादियोंको वार्ताकी मेजपर लाना था।

इस कमेटीमें तब सुप्रीम कोर्टके वकील अशोक भान, पूर्व कानून मंत्री शांति भूषण, पत्रकार दीलिप पडगांवकर एवं एम.जे. अकबर, पूर्व आईएफएस अधिकारी वी.के. ग्रोवर तथा जूरिस्ट फाली नारीमन भी शामिल थे। यह बदकिस्मती रही कि यह कमेटी भी संबंधोंपर जमी हुई बर्फको नहीं तोड़ पायी थी और कमेटीका स्थान राज्यपाल नरेंद्र नाथ वोहराने ले लिया। पूर्व गृह सचिव रहे एन.एन. वोहराने तब फरवरी २००३ में वार्ताकारका पद संभाला था। एन.एन. वोहरा भी कोई तीर नहीं मार पाये थे क्योंकि उनकी कोशिशोंको उस समय धक्का लगा था जब अलगाववादी नेता प्रधान मंत्रीके सिवाय किसी औरसे बात करनेको राजी नहीं हुए। वोहराकी नाकामीके बाद भी कश्मीरमें वार्ताके जरिये शांति लानेके प्रयासोंका सिलसिला केंद्र सरकार द्वारा जारी रखा गया था। उनके बाद भाजपाके वरिष्ठ नेता अरूण जेटलीको वार्ताकार नियुक्त किया गया। रॉ के पूर्व चीफ ए.एस. दुल्लतको भी इसमें शामिल कर लिया गया था लेकिन नजीता फिर वही ढाकके तीन पातवाला ही था। कांग्रेस नेतृत्ववाली संप्रग सरकारकी वर्ष २००२ में गोलमेज कांफ्रेंसमें अलगाववादियोंको शामिल करनेकी कोशिशके नाकाम रहनेके बाद तो अलगाववादी जैसे अड़ियल हो गये थे जिन्होंने उसके बाद किसी भी वार्ताकारकी कोशिशोंको कामयाब ही नहीं होने दिया। इतना जरूर था कि इन कोशिशोंके कई साल बाद वर्ष २०१० में जब कई महीनोंतक चले आंदोलनमें १२० से अधिक आम नागरिक सुरक्षा बलोंकी गोलियोंसे मारे गये थे तो केन्द्र सरकारने दीलिप पडगांवकर, एम.एम. अंसारी और प्रो. राधा कुमारको वार्ताकार नियुक्त कर कश्मीर सुलझानेकी ताजा कोशिश की थी। इस दलने अपने दौरों और मुलाकातोंके बाद अपनी रिपोर्ट तो केंद्र सरकारके पास जमा करवा दी थी लेकिन न ही कांग्रेस सरकार और न ही भाजपा सरकारने उन रिपोर्टोंको रोशनी दिखानेकी कोशिशतक की। ऐसेमें सवाल यही है कि ताजा वार्ताकारकी नियुक्ति क्या वाकई संबंधोंपर जमीं हुई बर्फको तोड़ पायगी और क्या वह कश्मीर मुद्देको सुलझा पायंगे।

यह हुर्रियतकी खुशफहमी है कि वही कश्मीरके असली और सच्चे प्रतिनिधि हैं, जबकि ऐसा बिलकुल भी नहीं है। कश्मीरके साथ जम्मू और लद्दाखके क्षेत्र भी जुड़े हैं। जम्मूके डोगरा, कश्मीरके ही पंडित और लद्दाखके लद्दाखी लोग हुर्रियतके साथ नहीं हैं। हुर्रियत श्रीनगरमें और आसपास सिर्फ एक ही तबके की बात करती रही है। हुर्रियत नेता कश्मीरपर मध्यस्थताके पक्षधर हैं-भारत, पाकिस्तान और हुर्रियत। यह व्यवस्था संयुक्त राष्ट्रसे लेकर किसी भी समझौतेमें नहीं है। हुर्रियत जिस संयुक्त राष्ट्र प्रस्तावकी दुहाई देता है, उसमें भी भारत-पाकिस्तानका ही जिक्र है। कोई तीसरा पक्ष नहीं! प्रस्तावपर कारवाईसे पहले यह प्रावधान है कि पाकिस्तान अपने कब्जेके भारतीय हिस्सेको भारतको पहले लौटायगा, उसके बाद कोई संवाद या कारवाई शुरू होगी तो फिर हुर्रियत बार-बार पाकिस्तानकी पैरोकारी क्यों करता है?

हुर्रियतसे भी बातचीत की इच्छा वार्ताकारने इसलिए जतायी है कि वह कश्मीरी अवामका हिस्सा हैं और भारतीय नागरिक भी हैं। यही नहीं अब तो वह प्रधान मंत्रीसे कम किसीसे भी बात करनेको राजी नहीं हैं। हुर्रियत कश्मीरके एक कोनेतक ही प्रासंगिक है, सियासी तौरपर वह 'शून्य' हैं। फिर भी नागरिकके तौरपर वह बातचीतमें शामिल होना चाहते हैं तो संवाद जरूर होना चाहिए। यदि हुर्रियत भारतीय संविधानके दायरेमें और तिरंगेको सलाम करते हुए बातचीत करना चाहेंगे तो उनका स्वागत किया जाना चाहिए। यदि अब भी वह पाकिस्तानपरस्त मान रहे हैं तो उनसे बातचीतके मायने क्या हैं? जब पाकिस्तानके प्रधान मंत्री शाहिद अब्बासीने कश्मीरकी आजादीकी मुहिमको बेमानी करार दे दिया, तो अब रोनेको कौन-सा कंधा रह गया है? भारत सरकारने साफ कर दिया है कि कोई आजादी नहीं, कोई स्वायत्तता नहीं, कश्मीरमें अमन-चैनके मद्देनजर बातचीतके सिलसिलेमें शामिल होना है तो स्वागत है। दरअसल वार्ताके दौरको व्यापक बनानेके लिए वार्ताकारने हुर्रियत नेताओंसे बात करनेकी इच्छा जतायी थी, लेकिन हुर्रियतने खुशफहमी यह पाल ली कि भारत सरकार उनके नखरे उठानेको तैयार है, लिहाजा उन्होंने नखरे दिखाने शुरू कर दिये। वार्ताकारको भी ज्यादा ईमानदार साबित करनेके लिए हुर्रियतका राग नहीं अलापना चाहिए।

अब विदेशों में बसना आसान नहीं

पिछले कई वर्षोंसे अमेरिकी सरकार विदेशियोंके अमेरिका आनेपर और उच्च शिक्षा प्राप्त कर वहीं बस जानेपर नियंत्रण लगा रही है। जबसे ट्रम्प राष्ट्रपति बने हैं, उन्होंने कई तरहकी पाबंदी लगा दी हैं।

❐ डा.गौरीशंकर राजहंस

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प राष्ट्रपतिने कहा है कि वह थोड़ेसे विदेशियोंको ही अमेरिका आनेकी इजाजत देंगे जिन्हें कोई हुनर प्राप्त हो। अन्य देशोंके साथ भारतपर भी इसका बहुत ही बुरा प्रभाव पड़ा है। परन्तु जब अमेरिकाके द्वार बंद हो गये तब भारतीय छात्रोंने आस्ट्रेलिया और कनाडाका रुख किया। कनाडामें तो अब भी उदारतापूर्वक उन भारतीयोंका स्वागत होता है जिनके पास कोई हुनर (स्किल) है। ज्यादातर उन युवकोंकी मांग होती है जिन्होंने आईटी (सूचना प्रोद्योगिकी) या बिजनेस मैनेजमेंटके क्षेत्रमें दक्षता प्राप्त की हो जिसका लाभ कनाडाकी सरकार और जनताको हो। परन्तु हालतक विदेशियोंके आनेमें और वहां बस जानेमें आस्ट्रेलियाकी सरकार बहुत ही उदार थी। आज भी हजारों भारतीय छात्र ऑस्ट्रेलियामें उच्च शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं और वहीं बस गये हैं। क्योंकि आम ऑस्ट्रेलियाई नागरिकका जीवन विकासशील देशोंके नागरिकोंकी तुलनामें बहुत ऊंचा है। परन्तु हालमें ऑस्ट्रेलियाके कई राजनेताओंने विदेशियोंके ऑस्ट्रेलिया आनेपर रोक लगानेकी मांग शुरू कर दी है। हालमें कई प्रमाणिक सर्वेक्षण हुए जिनसे यह पता चला कि ऑस्ट्रेलियाके हर तीन नागरिकोंमेंसे एक विदेशी है जो अपने देशको छोड़कर रोजगारकी खोजमें ऑस्ट्रेलिया आकर बस गया है।

इन प्रमाणिक सर्वेसे यह भी पता चला है कि १९७० की तुलनामें ऑस्ट्रेलियाकी जनसंख्या ७० प्रतिशत बढ़ गयी है। यह मुख्यतः विदेशियोंके ऑस्ट्रेलियामें आने और वहां बस जानेपर ही हुआ है। ७० के दशकसे ही ऑस्ट्रेलियामें परिवार नियोजनका पालन वहांकी जनता संख्तीसे करती आ रही है और हर परिवारमें दोसे कम बच्चे हैं। परन्तु जनसंख्याके बढ़ जानेका मुख्य कारण विदेशोंसे आये हुए वह लोग हैं जो जीविकाकी खोजमें पिछले अनेक वर्षोंसे ऑस्ट्रेलियामें आकर बस गये हैं। पहले कनाडा, न्यूजीलैंड, ब्रिटेन और अमेरिकामें विदेशी जीविकाकी खोजमें जाकर बसते थे। परन्तु उनकी तुलनामें ऑस्ट्रेलियामें लाखोंकी संख्यामें विदेशी आकर बस गये हैं जिसका प्रभाव यह पड़ा है कि जो ऑस्ट्रेलियाके मूल नागरिक हैं उनका जीवन स्तर बहुत नीचे गिर गया है। अनुमानके अनुसार सन् २००० से जितने विदेशी खासकर एशिया मूलके लोग ऑस्ट्रेलिया आये हैं उनकी संख्या दुगुनी हो गयी है। ऑस्ट्रेलियाके रिजर्व बैंकके गवर्नरने कहा है कि यदि विदेशियोंका इस तरह से ऑस्ट्रेलियामें आना नहीं रोका गया तो इसका ऑस्ट्रेलियाकी अर्थव्यवस्थापर बहुत ही बुरा असर पड़ेगा। पहलेकी तुलनामें ऑस्ट्रेलियामें बेरोजगारीकी दर छह प्रतिशत हो गयी है। हालके वर्षोंमें उस देशमें इतने बेरोजगार नहीं थे। इसके अलावा ऐसे लोगोंकी संख्या भी बहुत अधिक बढ़ गयी है जिन्होंने ऊंची डिग्री प्राप्त की हैं। परन्तु जीवनयापनके लिए छोटी-छोटी नौकरियां कर रहे हैं जैसे किसी होटल या रेस्तरांमें बेयराका काम करना। हालमें भारतके जो संपन्न लोग घूमनेके लिए आस्ट्रेलियाके बड़े शहरों सिडनी और मेलबोर्न आदिमें गये हैं, उन्हें यह देखकर बहुत ही दुख और आश्चर्य हुआ कि एमबीएकी डिग्री प्राप्त किये हुए युवक होटल और रेस्तरांमें बेयराका काम करते हैं। जब उनसे पूछा गया तो उन्होंने एक ही जवाब दिया कि इस देशमें श्रमका महत्व है। फिर यहां इतनी दूर हमें कौन पहचानता है कि हम किस तरह अपना जीवनयापन कर रहे हैं। यहांपर बेयरेके रूपमें भी काम करनेपर हजारों डालर महीना तनख्वाह मिल जाती है। ऐसी तनख्वाह उन्हें भारतमें कहीं नहीं मिलेगी और अब जब अमेरिका और ब्रिटेन सहित पश्चिमके देशोंने भारतीयोंके 'इमीग्रेशन' पर रोक लगा दी है और उन्हें लम्बी अवधिका वीजा नहीं दिया जा रहा है तो वह भला कहां जायं? बात कुछ हद तक ठीक ही है। परन्तु प्रश्न है कि यदि यह युवक भारत लौट गये तो उन्हें उनकी डिग्रीके अनुसार नौकरी कहां मिलेगी?

सर्वेमें यह पाया गया कि ऑस्ट्रेलियाके स्कूल, कालेजों और विश्वविद्यालयोंमें विदेशी छात्रोंकी संख्या सबसे अधिक है। गत वर्ष विदेशसे आये हुए छह लाख छात्र ऑस्ट्रेलियामें विभिन्न शिक्षा संस्थानों खासकर विश्वविद्यालयोंमें उंच्च शिक्षा प्राप्त कर रहे थे। अधिकतर छात्र ऊंची शिक्षा प्राप्त करनेके लिए पैसे अपने देशसे लाते थे। गत वर्ष उन्होंने १५ बिलीयन डालर अपनी शिक्षापर खर्च किया। आस्ट्रेलियामें कहा जाता है कि जिस तरह वहांके शिक्षा संस्थानोंमें युवक आ रहे हैं उससे तो ऐसा लगता है कि शिक्षा ही ऑस्ट्रेलियाका मुख्य 'निर्यात' बन गया है। परन्तु अब उसमें पेंच यह फंस गया है कि पहले तो यवुक उच्च शिक्षा प्राप्त कर आस्ट्रेलियामें कोई न कोई नौकरी खोजकर वहीं बस जाते थे। परन्तु अब ऐसा करना संभव नहीं है। एशियाई मूलके लोगोंपर ऑस्ट्रेलियाके मूल निवासियोंने अनेकों बार जानलेवा हमले किये हैं।

अत्यधिक विदेशियोंके आनेके बावजूद भी ऑस्ट्रेलियाका अधिकतर भाग घनी आबादीवाला नहीं है। क्योंकि ऑस्ट्रेलियाका अधिकतर भूभाग सदियोंसे बंजर रहा है। इसका लाभ उठाकर बिल्डर बड़ी ऊंची कीमतमें लोगोंको फ्लैट देते हैं। ऑस्ट्रेलियाकी सरकार अब बिल्डरोंपर नकेल कस रही है जिससे मूल निवासियोंको रहनेके लिए जगह मिलनेमें कठिनाई नहीं हो। ऑस्ट्रेलियामें संसदमें और संसदके बाहर यह मांग हो रही है कि विदेशियोंके आनेपर रोक लगनी चाहिए। इसके लिए ऑस्ट्रेलियाई सरकारने उन्हीं लोगोंको वीजा देनेका फैसला किया है जिन्हें कोई हुनर प्राप्त हो। इस तरहकी पाबंदी लगानेपर अब भविष्यमें भारतीय मूलके लोग हजारोंकी संख्यामें ऑस्ट्रेलिया जाकर शिक्षा प्राप्त कर वहां नहीं बस सकेंगे। यह एक नयी समस्या उत्पन्न हो गयी है जिसपर अविलंब ध्यान देनेकी आवश्यकता है। जरूरत इस बातकी है कि जो लोग ऑस्ट्रेलिया जाकर बसना चाहे वह भारतमें ही कोई अच्छा हुनर प्राप्त कर लें। क्योंकि अनेकों सर्वेमें कहा जा रहा है कि अब ऑस्ट्रेलियामें भारतीय मूलके आईटी प्रोफेसनल या एमबीएकी भरमान हो गयी है। अब उनके लिए वहां कोई जगह नहीं है। इस समस्यापर गंभीरतापूर्वक विचार करनेकी आवश्यकता है।

आत्मबोध

धर्म मार्ग की प्रेरणा

❐ श्रीराम शर्मा

एक बार विष्णु भगवानका मन पृथ्वीपर आकर मनुष्योंकी स्थितिका पर्यवेक्षण करने और धर्म मार्गपर चलनेकी प्रेरणा देनेका हुआ। वह चलने लगे तो लक्ष्मीजीने रोका और कहा, प्रभु! मनुष्य अब अपने चिंतन, चरित्रकी दृष्टिसे बहुत ही गये-गुजरे हो गये हैं। वह धर्मके बातें तो करते है, परन्तु उन्हें हृदयंगम करनेको बिलकुल भी तैयार नहीं हैं। ऐसी दशामें आपका उनके पास जाना व्यर्थ है। विष्णुजी माने नहीं। लक्ष्मीजी अपनी बातकी अवहेलना किये जानेपर रुष्ट हो गयी बोली, यदि धर्म शिक्षा मनुष्योंने स्वीकार न की, आप असफल लौटे तो मैं घरमें न आने दूंगी। विष्णु चले गये। जगह-जगह जाकर उन्होंने मनुष्योंको एकत्रित किया, धर्म, कर्मकी शिक्षा दी। लोगोंने सभी जगह एक-सा उत्तर दिया कि यह तो हम कथा, वार्ताओंमें सुनते रहते हैं। यदि आपकी वस्तुतः कृपा है तो हमारी मनोकामनाएं पूरी करें। निराश होकर भगवान दूसरी, तीसरी, चौथी जगह गये, परन्तु सर्वत्र एक जैसे ही उत्तर मिले। खिन्न होकर वह जहां-तहां छिपते भी फिरे परन्तु लोगोंने उन्हें ढूंढ़ ही लिया और किसी प्रकारकी शिक्षा देनेकी अपेक्षा मनोरथ पूर्ण करनेकी बात ही कही। मनःस्थिति बदलनेपर परिस्थिति बदलती है, मनुष्य अपने भाग्यका निर्माता आप है, जैसी शिक्षाएं उन्हें बिलकुल नहीं सुहा रही थी। ऐसी अवज्ञा देखकर भगवान बड़े दुःखी हुए। कहां तो वह अपने भक्तोंको ढूंढ़ने चले थे। मनमें उमंग थी कि धर्म परायण बननेकी लोगोंको शिक्षा देंगे। परन्तु वहां तो सब कुछ उल्टा है। खिन्न मनसे पृथ्वी लोकमें विचरण करते-करते आदमी नामक प्राणीसे जान बचाते वह समुद्रके बीच एक टापूपर द्वारिका जैसी नगरीमें एकांत स्थानपर जा छिपे। उन्होंने मनुष्योंसे पुनः संपर्क कर उन्हें सत्य पथपर चलनेकी प्रेरणा देनेका विचार ही त्याग दिया। भगवानके परम भक्तोंमें नारदको सर्वश्रेष्ठ स्थान मिला हुआ है। वह तीनों लोकोंमें विचरण करते रहते है। नारदजी बैकुंठ लोकसे खबर लेकर निकले कि विष्णु भगवान धरतीपर गये है। अपनी श्रद्धाके बलपर उन्होंने भगवानको खोज ही लिया। उन्हें उदास देखकर नारदजीने कारण पूछा, भगवानने अपनी व्यथा कह सुनायी और करुण स्वरमें बोले, हे देवर्षि! कोई ऐसा स्थान बताइये जहां मैं छिप सकूं। नारदजीने सारा वृत्तांत सुना, कुछ सोचे और बोल उठे, भगवन! मार्ग मिल गया। आप मनुष्यके हृदयमें जा बैठिये। लोग तो आपको बहिर्मुखी होनेके कारण जगह-जगह ढूंढ़ते फिरते हैं। वह आपको उनके ही अंदर विराजमान होनेकी कल्पनातक न कर पायंगे। जो आपका सच्चा भक्त होगा, वह जब भी अपने अंदर आपको ढूंढ़ेगा, आपको पा लेगा। उसीको आप सन्मार्गपर चलनेका, भवबंधनोंसे मुक्त हो स्वर्गप्राप्तिका मार्ग बताते रहियेगा। आप तो मायापति है प्रभु! एकसे अनेक बनकर हृदय क्षेत्रमें जा बैठिये। देवी लक्ष्मी कभी आपसे दूर रह सकेंगी वह भी नकली भक्तोंसे व्यथित हैं। वह भी आपके साथ ही रहेंगी। भगवानको सलाह पसंद आ गयी। वह मनुष्योंके हृदयमें तबसे बैठे हैं। परन्तु सभी उन्हें ढूंढ़ते बाहर तीर्थ, देवालयोंकी दौड़ लगाते रहते हैं। समय, श्रम एवं पैसा गंवाते हैं फलतः भगदड़से निराशा ही निराशा हाथ लगती है।

रोहिंग्या मुसलमान बन रहे देश के लिए समस्या

❐ विजय कुमार

रोहिंग्या मुसलमान इन दिनों केवल भारत ही नहीं, तो बंगलादेशके लिए भी सिरदर्द बन गये हैं। यह लोग मूलतः बंगलादेशी ही हैं, जो म्यांमारके सीमावर्ती क्षेत्रमें रहते हैं। काम-धंधेके लिए म्यांमार आते-जाते हुए हजारों परिवार वहांके अराकान या रखाइन क्षेत्रमें बस गये, जो आज लाखों हो गये हैं। आज तो भारत, बंगलादेश और बर्मा अलग-अलग देश हैं। परन्तु १९३५ तक भारत, म्यांमार और श्रीलंकाका एक ही गर्वनर जनरल (वायसराय) होता था। ब्रिटिश संसदने 'गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट १९३५' से इन्हें अलग किया, परन्तु लम्बे समयसे वहां रहनेके बावजूद म्यांमार इन्हें अपना नागरिक नहीं मानकर अब निकाल रहा है। इसीसे यह संकट उत्पन्न हुआ है। इसका कारण यह है कि कबीलाई जीवन होनेके कारण हिंसा, लड़कियां उठाना और दूसरोंके धर्मस्थल तोड़ना इनकी स्वाभाविक वृत्ति है।

म्यांमार एक बौद्ध देश है। बौद्ध समुदाय अहिंसक और शांतिप्रिय है। काफी समयसे वह लोग इनके उपद्रव सह रहे थे परन्तु जब पानी सिरसे ऊपर हो गया तो उन्हें लगा कि अब भी यदि चुप रहे तो हम अपने देशमें ही अल्पसंख्यक हो जायंगे। फिर हमारी दशा ऐसी ही होगी, जैसी बंगलादेश और पाकिस्तानमें हिन्दुओंकी है। अतः कुछ लोग शस्त्र लेकर इनपर कूद पड़े। इनके नेता हैं मांडलेके बौद्ध भिक्षु आशिन विराथु। वह पिछले १५ सालसे इसमें लगे हैं। यद्यपि इसके लिए उन्हें २५ सालकी सजा भी हुई परन्तु जनताके दबावमें सरकारको इन्हें सात साल बाद ही छोड़ना पड़ा। बाहर आकर यह फिर उसी काममें लग गये हैं। द्वितीय विश्व युद्धमें ब्रिटेनने रोहिंग्याओंको जापानके विरुद्ध लड़नेको शस्त्र दिये थे। उन्होंने कहा कि जीतनेपर वह रोहिंग्याओंके लिए एक अलग मुस्लिम देश बना देंगे। लेकिन शस्त्र पाकर वह हिन्दुओं और बौद्धोंका संहार करने लगे। केवल एक ही दिनमें उन्होंने २० हजार बौद्धोंको मार डाला। हत्या और हिंसाका यह तांडव आगे भी चलता रहा।

सन् १९४६ में स्वतंत्र होते ही म्यांमारकी सेनाने इनके विरुद्ध कारवाई कर इनकी कमर तोड़ दी। अतः यह शांत हो गये परन्तु १९७१ में बंगलादेश बननेपर कई आतंकी समूह बनाकर यह फिर सक्रिय हो गये। दुनियाके अधिकांश मुस्लिम देशोंने इन्हें समर्थन और पड़ोसी बंगलादेशने इन्हें शस्त्र दिये। इस प्रकरणके बाद आशिन विराथु सक्रिय हुए। एक बौद्ध महिलाके बलात्कार एवं हत्यासे पूरा देश भड़क उठा और फिर हर बौद्ध विराथुका समर्थक बन गया। म्यांमारकी शासन प्रमुख आंग सान सूकी नोबेल विजेता एवं मानवाधिकारवादी हैं परन्तु म्यांमारका जमीनी सच देखकर उन्होंने भी रोहिंग्याओंको कहा है कि वह या तो शांतिसे रहें या कोई दूसरा देश देख लें। म्यांमारमें सेनाको अनेक शासकीय अधिकार भी हैं। उनकी इच्छाके बिना संसद कुछ नहीं कर सकती। सेना रोहिंग्याओंको सबक सिखाना चाहती है। अतः वह इन्हें खदेड़ रही है। इससे यह यहां-वहां भाग रहे हैं। बंगलादेशके मूल नागरिक और वहां रिश्तेदारी होनेसे अधिकांश लोग वहीं जा रहे हैं। कुछ समुद्री मार्गसे सऊदी अरब, यूएएई। पाकिस्तान, थाइलैंड, मलयेशिया, इंडोनेशिया आदिमें भी गये हैं। भारतमें इनकी संख्या ४०००० से चार लाखतक कही जाती है। भारतमें जो रोहिंग्या हैं, वह हर जगह अपने स्वभावके अनुसार आसपासकी खाली सरकारी जगह घेरकर मस्जिद और मदरसे आदि बना रहे हैं। हर दम्पतिके पास छह-सात बच्चे भी हैं। अतः उनके आवासके पास गंदगी रहती है। सघन बस्तियोंमें उन्होंने कुछ दुकानें भी बना ली हैं। कुछ लोग मजदूरी आदि करने लगे हैं। इससे जहां एक ओर भारतीय संसाधनोंपर बोझ बढ़ रहा है, वहां वह भारतीयोंका रोजगार भी छीन रहे हैं। अर्थात जो स्थिति बंगलादेशी घुसपैठियोंकी है, वही क्रमशः इनकी हो रही है। अतः विस्फोटक होनेसे पहले ही समस्या सुलझानी होगी। लेकिन यह हो कैसे। सर्वप्रथम तो दुनिया सब मुस्लिम देश दो-चार हजार करके अपने मजहबी भाइयोंको आपसमें बांट लें। भारत उन्हें वहांतक पहुंचा दे या फिर यह सब हिन्दू या बौद्ध हो जायं।

भारत एक हिन्दू देश है। बौद्ध मत भी विशाल हिन्दू धर्मका ही अंग है। इससे भारतीयोंकी स्वाभाविक सहानुभूति उन्हें मिलेगी। मंदिर जानेसे उनकी हिंसा और उग्रता घटेगी। २०-३० सालमें वह अपने कुसंस्कारोंसे मुक्त हो जायंगे। दिल्लीमें कुछ रोहिंग्या चर्चका आर्थिक और सामाजिक सहयोग पानेको ईसाई हो गये हैं। जब वह ईसाई हो सकते हैं तो अपने पुरखोंके पवित्र हिन्दू धर्ममें भी आ सकते हैं। दूसरा रास्ता उन्हें निकालनेका है। यह बात कई केन्द्रीय मंत्रियोंने कही है, परन्तु यह आसानीसे तो जायंगे नहीं। सरकार तो कई पार्टियोंकी बनीं परन्तु आजतक बंगलादेशी घुसपैठिये वापस नहीं भेजे गये। जो बात तब सच थी, वह आज भी सच है। इसलिए सेक्यूलरोंके शोरपर ध्यान न देकर सख्ती करनी होगी। भारत सरकार इन्हें पकड़कर सौ-सौके समूहमें नौकाओंमें बैठा दे। मानवताके नाते साथमें कुछ दिनका खाना, पानी और बच्चोंके लिए दूध आदि रखकर इन्हें भारतीय समुद्री सीमाके पार छोड़ दिया जाय। फिर जहां इनकी किस्मत इन्हें ले जाय, यह वहीं चले जायं।